आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)

शुक्रवार 26.09.2025 समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड में पंजीकृत 5 हजार 388 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को लेकर स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं; अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने वक्फ संपत्तियों के समयबद्ध पंजीकरण और प्रबंधन पर दिया जोर।
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में नकल की शिकायतों की जांच न्यायिक निगरानी में की जाएगी।
- उधमसिंह नगर जिले में गदरपुर–दिनेशपुर–मटकोटा–हल्द्वानी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू।
- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने हरिद्वार कुम्भ 2027 से जुड़े स्थायी और अस्थायी कार्यों की प्राथमिकता तय कर नोडल अधिकारियों की जल्द तैनाती करने को कहा।

वक्फ संपत्ति अतिक्रमण

उत्तराखंड में पंजीकृत 5 हजार 388 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को लेकर स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते की अध्यक्षता में देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में यह जानकारी सामने आई। बैठक में डॉ. धकाते ने वक्फ संपत्तियों के समयबद्ध पंजीकरण और प्रबंधन पर जोर देते हुए कहा कि सभी संपत्तियों का विवरण भारत सरकार के 'उम्मीद पोर्टल' पर दर्ज होना चाहिए। साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि राज्य में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में हैं। पर्वतीय जिलों में इनकी संख्या कम है। वक्फ संपत्तियों में बिल्डिंग, दुकानें, मकान, कब्रिस्तान, मस्जिदें, मदरसे और अन्य श्रेणियां शामिल हैं।

डॉ. धकाते ने बताया कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि वक्फ बोर्ड पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड तैयार करे और नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि सभी वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।

गौरतलब है कि राज्य सरकार अब तक सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों से नौ हजार एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा चुकी है।

निर्णय

उत्तराखंड सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में नकल की शिकायतों की जांच न्यायिक निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

न्यायमूर्ति वर्मा, एसआईटी की जांच की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। उन्हें आवश्यकतानुसार जिलों का दौरा कर शिकायतों और सूचनाओं का संज्ञान लेने तथा एसआईटी को मार्गदर्शन देने का अधिकार दिया गया है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 24 सितम्बर को पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता देहरादून की पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जया बलूनी करेंगी। यह टीम राज्यभर में नकल प्रकरण की जांच कर दोषियों की पहचान करेगी।

समीक्षा

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने 2026 में होने वाली नंदादेवी राजजात यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने चमोली के जिलाधिकारी को सभी विभागों और हितधारकों के साथ समन्वय कर यात्रा को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिये मानक संचालन प्रक्रिया शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि यात्रा की ऐतिहासिकता और विशिष्टता से कोई छेड़छाड़ न हो और इसकी डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की जाए। उन्होंने अत्यधिक वर्षा से प्रभावित मार्गों और पड़ावों की रेकी कर उन्हें दुरुस्त कराने, साथ ही टेंट और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यात्रा के सभी स्थायी और अस्थायी कार्यों की प्राथमिकताएं तय कर तत्काल शुरू करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग को प्रत्येक पड़ाव और मार्ग पर चिकित्सक, दवाएं, पोर्टेबल ऑक्सीजन और उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने विद्युतीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, भीड़ प्रबंधन, खाद्य सामग्री, ठोस अपशिष्ट और स्वच्छता प्रबंधन को शामिल करते हुए व्यापक एसओपी बनाने पर जोर दिया।

शहीद सम्मान यात्रा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद राइफलमैन नरेश कुमार के सहस्त्रधारा रोड स्थित गुजराड़ा मानसिंह आवास से ''शहीद सम्मान यात्रा'' के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से भेंट कर उनके आंगन की पावन मिट्टी एकत्र की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह यात्रा उन वीर सपूतों को समर्पित है, जिनका अदम्य साहस और बलिदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने बताया कि शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिये राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देहरादून में निर्माणाधीन सैन्य धाम के लिए अब तक एक हजार 734 शहीदों के घरों से मिट्टी एकत्र की जा चुकी है। 25 सितम्बर से 4 अक्टूबर तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान और भी शहीद परिवारों से मिट्टी एकत्र की जाएगी, जिसे 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में सम्मिलित किया जाएगा। इस समारोह में शहीद परिवारों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।

उद्घाटन

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना ''आदि कर्मयोगी अभियान'' के अंतर्गत चकराता के मोहना गांव में ''आदि सेवा केंद्र'' का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी रवि शेखर ने भाग लिया और ग्रामीणों से वार्ता की।

उन्होंने ग्रामीणों को पलायन रोकने के लिए कृषि और होमस्टे से संबंधित योजनाएं अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इससे गांव में स्वरोजगार बढ़ेगा और पलायन पर रोक लगेगी।

शिलान्यास

केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत ऊधमसिंह नगर जिले में गदरपुर–दिनेशपुर–मटकोटा–हल्द्वानी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास 55 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना तराई क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसके पूरा होने से लगभग 2 लाख लोगों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही व्यापार, उद्योग और

पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह मार्ग उत्तराखंड के गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, छतरपुर को उत्तर प्रदेश के विलासपुर से जोड़ेगा।

समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में हरिद्वार कुम्भ 2027 की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि कुम्भ मेले से जुड़े स्थायी और अस्थायी कार्यों की प्राथमिकता तय की जाए और नोडल अधिकारियों की तैनाती शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

सिंचाई विभाग को नहर बंदी के समय कराए जाने वाले कार्य समय से पूरे करने और उत्तर प्रदेश से संवाद कर नहर बंदी की अवधि बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने पर भी जोर दिया।

उन्होंने रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और जीआरपी थानों में मानक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस और रेलवे विभाग को संयुक्त रूप से यातायात प्लान बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस का सर्विलांस सिस्टम और अस्थायी थानों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि कुम्भ के दौरान घाटों की सफाई बड़ी चुनौती होगी, इसके लिए विशेष प्रणाली विकसित की जाए। उन्होंने सभी विभागों को कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस की व्यवस्था करने को भी कहा।

यूसीसी क्रियान्वयन समीक्षा

गृह सचिव शैलेश बगौली ने सचिवालय से सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समान नागरिक संहित–यूसीसी के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी विभिन्न मंचों के माध्यम से लोगों को जागरूक करें और उन्हें विवाह पंजीकरण अनिवार्य रूप से यूसीसी के अंतर्गत कराने के लिए प्रेरित करें।

सचिव ने बताया कि आगामी 27 जनवरी 2026 को पहला ''यूसीसी दिवस'' मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रत्येक जिले में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने जिलाधिकारियों से कार्यक्रम की रूपरेखा के लिये सुझाव भी मांगे।

उन्होंने कहा कि मानसून के बाद ग्राम स्तर पर फिर से यूसीसी से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए और विशेष शिविर लगाए जाएं। जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत विवाह पंजीकरण होगा, उनके ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा।

सचिव ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिलाधिकारियों ने अपने–अपने क्षेत्रों की प्रगति और व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी साझा की।

हाइटेक कॉमन्स सर्विस पॉइंट्स

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल पर जिले में सभी कॉमन्स सर्विस पॉइंट्स–कॉप्स को आधुनिक और हाईटेक बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस क्रम में चकराता, त्यूनी, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर, डोईवाला और ऋषिकेश में स्थित कॉप्स को कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कॉप्स को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करना आवश्यक है, ताकि आमजन को शासन–प्रशासन से जुड़ी सेवाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण रूप से उपलब्ध हो सकें। अब कॉप्स के माध्यम से प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, राजस्व सेवाएं और अन्य सरकारी सेवाएं आसानी से प्राप्त की जा सकेंगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कॉप्स संचालकों को नई तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि आधुनिक उपकरणों का बेहतर उपयोग हो और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो।

फिल्म कार्यशाला

उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यधिकारी बंशीधर तिवारी ने देहरादून में पांच दिवसीय एक्टिंग कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज राज्य में फिल्म शूटिंग और फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के अनुसार नई फिल्म नीति लागू की गई है, जो अन्य राज्यों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखण्ड में अनुदान धनराशि ज्यादा दी जा रही है।

मुख्य समाचार एक बार फिर–

- उत्तराखंड में पंजीकृत 5 हजार 388 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को लेकर स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं; अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने वक्फ संपत्तियों के समयबद्ध पंजीकरण और प्रबंधन पर दिया जोर।
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में नकल की शिकायतों की जांच न्यायिक निगरानी में की जाएगी।
- उधमसिंह नगर जिले में गदरपुर–दिनेशपुर–मटकोटा–हल्द्वानी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू।
- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने हरिद्वार कुम्भ 2027 से जुड़े स्थायी और अस्थायी कार्यों की प्राथमिकता तय कर नोडल अधिकारियों की जल्द तैनाती करने को कहा।